

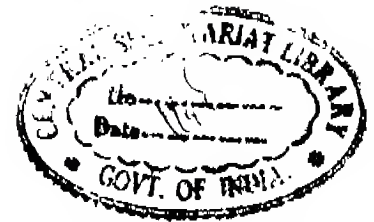


# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 45 ]  
No. 45]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, फरवरी 22, 1996/फाल्गुन 3, 1917  
NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 22, 1996/PHALGUNA 3, 1917

वित्त मंत्रालय  
( राजस्व विभाग )

संकल्प

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 1996

**फा० सं० 22/6/95-विक्री कर.**—दिनांक 2 दिसम्बर, 1995 को हुए वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में राज्यों के वित्त मंत्रियों की समिति की रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट मुख्य सिफारिश को लागू करने और जिन पर राज्यों के बीच सहमति थी, का अनुश्रवण करने के लिए एक समिति के गठन की सिफारिश का संकल्प पारित किया गया था। यह भी निर्णय लिया गया था कि राज्यों के वित्त मंत्रियों की वर्तमान समिति को यह कार्य सौंपा जाना चाहिए।

2. संकल्प के अनुसरण में सरकार ने, राज्यों के वित्त मंत्रियों की समिति को ऐसी मुख्य सिफारिशों को लागू करने का अनुश्रवण करने का कार्य सौंपने का निर्णय लिया है।

3. समिति अपने कार्य के लिए अपनी कार्य विधि तैयार करेगी और राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से आवश्यक सूचना मंगवा सकती है।

4. अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए समिति बिहार अथवा किसी अन्य राज्य के वित्त मंत्री अथवा किसी अन्य विशेषज्ञ की सदस्य के रूप में सहायता ले सकती है।

5. राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान इस समिति को सचिवालयीय सहायता प्रदान करेगा।

6. सभी राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार की सूचना के लिए समिति सिफारिशों को लागू करने की प्रगति पर तिमाही रिपोर्ट तैयार करेगी।

एन० एन० मुखर्जी, अपर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

RESOLUTION

New Delhi, the 20th February, 1996

**F.No. 22/6/95-ST.**—The Finance Ministers Conference held on 2nd December, 1995 had adopted a resolution recommending constitution of a Committee for monitoring the implementation of major recommendation contained in the report of the Committee of State Finance Ministers and on which there was agreement among States. It was also decided that the present Committee of State Finance Ministers should be entrusted with this job.

2. In pursuance of the resolution, Government has decided to entrust the job of monitoring of the implementation of such major recommendations to the Committee of State Finance Ministers.

3. The Committee will evolve its own procedures for its work and may call for information as may be necessary from State Governments/Union Territories.

4. The Committee may co-opt Finance Minister of Bihar or of any other State or any other expert as a member to facilitate its work.

5. The National Institute of Public Finance & Policy will provide secretarial assistance to the Committee.

6. The Committee will prepare quarterly reports on the progress of implementation of recommendations for information of all the State Governments and the Central Government.

N.N. MOOKERJEE, Addl. Secy.